पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रवि कांत

बनाम

बंदना कुमारी

2020 की विविध अपील संख्या **248**
10 नवंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता का उत्तरवादी के साथ विवाह उसकी सहमति के बिना और दबाव में किया गया था?
क्या विवाह धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के विपरीत संपन्न हुआ था
क्या विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) के तहत निरस्त किए जाने योग्य है?

हेडनोट्स

यद्यपि आदेश पत्र में ऐसा उल्लेख है, तथापि कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया गया था। (पैरा 6) यहां तक कि डिक्री के अभाव में भी, परिवार न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी जा सकती है और ऐसी अपील को विविध अपील के रूप में माना जाएगा। (पैरा 8) यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पक्षकारों को विवादास्पद तथ्यों की जानकारी थी और उन्होंने उसी के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत किए। साथ ही, वैवाहिक वाद वर्ष 2013 में ही दायर किया गया था और अब एक दशक से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ऐसे में, यदि उन्हें पुनः परिवार न्यायालय की प्रक्रिया में वापस भेजा जाए, तो यह उनके प्रति कठोरता होगी। (पैरा 11) याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट किया है कि उसने तत्काल संबंधित प्राधिकरण के समक्ष क्यों नहीं गया, और इसमें कोई अनुचित विलंब नहीं है। जब परिवार न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि फ़ोटोग्राफ की जांच नहीं की गई है, तो उस स्थिति में न्यायालय के लिए उन दस्तावेजों पर भरोसा करना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि 'सप्तपदी' संस्कार का संपादन न होना यह नहीं दर्शाता कि विवाह हुआ ही नहीं था — ऐसा निष्कर्ष विधिक दृष्टिकोण से दुर्बल और निराधार है। (पैरा 36) उत्तरवादी के लिखित उत्तर में कई बिंदुओं पर मौन है और अस्वीकारोक्तियाँ टालमटोलपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पक्ष के साक्ष्य में यह बात आई है कि विवाह का वास्तविक प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि विवाह की रात को ही याचिकाकर्ता वहां से भाग गया था। इस तथ्य का उत्तरवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं किया गया है, यद्यपि यह कहा गया है कि वह विवाहोपरांत ससुराल गई थी, परंतु जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, उसने इस संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। (पैरा 37) अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा 39)

न्याय दृष्टान्त

सुनीता कुमारी बनाम प्रेम कुमार, 2009 (3) पी.एल.जे.आर. 990; नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम संपति

सुब्बा राव, एआईआर 1963 SC 884 ; सरोजा बी.आर. बनाम एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, बेंगलुरु, 1988 एस.सी.सी. ऑनलाइन कर्नाटक 419 ; भास्कर गांगुली उर्फ वास्कर गांगुली एवं अन्य बनाम सुजीत कुमार गुप्ता, 1995(2) पी.एल.जे.आर. 563 ; ग्यान चंद एंड ब्रदर्स बनाम रत्तन लाल उर्फ रत्तन सिंह, 2013 (2) एस.सी.सी. 606 ; एस. नागालिंगम बनाम शिवगामी, (2001) 7 एस.सी.सी. 487 ; 2013(2) एस.सी.सी. 606

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ; परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 ; भारतीय दंड संहिता, 1860 ; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

जबरन विवाह ; हिंदू रीतियाँ और परंपराएँ ; सप्तपदी ; विवाह निरस्तीकरण ; दबाव में प्राप्त सहमति ; वैवाहिक विवाद ; परिवार न्यायालय की डिक्री ; प्रमाण का भार ; शिकायत में विलंब ; दहेज आरोप

प्रकरण से उत्पन्न

परिवार न्यायालय, लखीसराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020, वैवाहिक वाद सं. 51 / 2013 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री जितेन्द्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता ; श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता ; श्री रवि रॉय, अधिवक्ता ; श्री श्रेयश गोयल, अधिवक्ता ; श्री अभय नाथ, अधिवक्ता ; सुश्री श्वेता राज, अधिवक्ता

उत्तरदायी की ओर से: श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनॉट्स बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 की विविध अपील संख्या **248**

= =

रवि कांत, पिता– चंद्र मौलेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी– ग्राम– रावरा, थाना– काशीचक, जिला नवादा।

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बंदना कुमारी, पिता– बिपिन सिंह, निवासी– गाँव– चौकी, पोस्ट– बालगुदर, थाना– लखीसराय, जिला– लखीसराय

... ... उत्तरदाता/ओं

==
========== उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः	श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता श्री रवि रॉय, अधिवक्ता श्री श्रेयश गोयल, अधिवक्ता श्री अभय नाथ, अधिवक्ता सुश्री श्वेता राज, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिएः	श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता

==
==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय **न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा**

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय श्री जस्टिस अरुण कुमार झा)

दिनांक : 10-11-2023

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनवाई की पिछली तारीख को सुना गया है।

02. याचिकाकर्ता/अपीलार्थी द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत 2013 के वैवाहिक मामला संख्या 51 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीसराय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ तत्काल विविध अपील दायर की गई है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(सी) सहपठित हिंदू विवाह नियम, 1956 के नियम 6 के तहत विवाह को रद्द करने के आदेश के लिए दायर याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

03. याचिकाकर्ता/अपीलार्थी का मामला जैसा कि अभिलेख से प्रतीत होता है, यह है कि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी संचार धारा 'ए' में एक सिपाही है। 30.06.2013 को याचिकाकर्ता अपने चाचा के साथ पूजा के लिए लखीसराय के अशोक धाम मंदिर गया था। जब याचिकाकर्ता और उसके चाचा लगभग 02 बजे पूजा के लिए सामग्री खरीद रहे थे तभी गांव- चौकी, पोस्ट- बालगुदर, थाना और जिला- लखीसराय के तीन व्यक्ति राजेश कुमार, दीपक कुमार और बिपिन सिंह पिस्तौल और चाकू से लैस छह अज्ञात व्यक्तियों के साथ आए और याचिकाकर्ता और उसके चाचा को घेर लिया। ये लोग उत्तरवादी को याचिकाकर्ता के पास लाए और बंदूक की नोक पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे उत्तरवादी के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता द्वारा विरोध दिखाए जाने पर, उन पर थप्पड़ और मुट्ठी से

हमला किया गया। याचिकाकर्ता के चाचा को भी उपरोक्त व्यक्तियों ने घेर लिया और धमकी दी। उपरोक्त उल्लेखनीय व्यक्तियों की अभिरक्षा में होने के रूप में कोई रास्ता नहीं पाते हुए, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी के सिर पर सिंदूर लगा दिया, लेकिन बिना किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्कार और अनुष्ठान के। तथाकथित विवाह के निष्पादन के बाद, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी को उपरोक्त बिपिन सिंह के घर में एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। याचिकाकर्ता के चाचा को भी धमकाया गया और बिपिन सिंह के घर में नजरबंद कर दिया गया। सूर्यास्त के बाद, याचिकाकर्ता के चाचा को रिहा कर दिया गया और उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ उत्तरदाता के लिए गहने और कपड़े के साथ आने के लिए कहा गया क्योंकि शादी हो चुकी है। इसके बाद, याचिकाकर्ता के चाचा लखीसराय पुलिस स्टेशन गए और दिनांक 01.07.2013 को लगभग 02 बजे पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उसी रात याचिकाकर्ता किसी तरह उत्तरवादी के घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा जो उपरोक्त बिपिन सिंह की बेटी है और घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने गया लेकिन फिर से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद याचिकाकर्ता अपने गांव पहुंच गया। चूंकि याचिकाकर्ता को तुरंत अपनी ड्यूटी में शामिल होने की आवश्यकता थी, इसलिए वह अपने सेवा स्थल पर गया और छुट्टी मिलने के बाद वह यह मामला दर्ज करने आया। इस बीच, याचिकाकर्ता के चाचा ने भी भ.द.स. की धारा 323, 341, 352, 387 और 365 के तहत परिवाद मामला संख्या 431 सी/12 के माध्यम से विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय की अदालत में एक आपराधिक मामला दायर किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि तथाकथित विवाह धार्मिक और प्रथागत कानूनों का उल्लंघन है और अमान्य है क्योंकि याचिकाकर्ता को धमकी और जबरदस्ती के तहत उत्तरवादी के सिर पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है और विद्वान परिवार न्यायालय से प्रार्थना की है कि वह विवाह को अमान्य घोषित करते हुए उसे निरस्त कर दे।

04. प्रत्यर्थी पेश हुई और अपना लिखित बयान दाखिल किया। अपने लिखित बयान में, उत्तरवादी ने प्रस्तुत किया कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी है और उनकी शादी हिंदू रीति–रिवाजों के तहत 30.06.2013 पर हुई और शादी के समय, उत्तरवादी के पिता ने याचिकाकर्ता को उपहारस्वरुप, सोना, रु 10,00,000 (दस लाख) नगद और अन्य सामग्री दिया। उत्तरवादी अपने वैवाहिक घर गई और कुछ

समय बीतने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक मारुति कार की मांग की और उत्तरवादी को प्रताड़ित किया। प्रत्यर्थी ने अपनी याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि उसने 2015 की परिवाद मामला संख्या 599 सी के माध्यम से भ.द.स. की धारा 498 के तहत एक परिवाद मामला दर्ज किया है जो विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय की अदालत में लंबित था।

05. प्रतिद्वंद्वी विवादों के आधार पर, वाद बिन्दु को तैयार करने की आवश्यकता थी। विद्वान परिवार न्यायालय की दिनांकित 19.02.2016 की आदेश पत्रक से पता चलता है कि सुलह की विफलता के बाद, वाद बिन्दु तैयार किए गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बनाए गए वाद बिन्दु रिकॉर्ड में नहीं हैं। यहां तक कि आक्षेपित निर्णय में भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है कि क्या कभी कोई वाद बिन्दु तैयार किया गया था और वे वाद बिन्दु क्या थे। यदि वाद बिन्दु को तैयार नहीं किया गया था, तो यह विद्वान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का दायित्व था कि वह बाद के चरण में भी वाद बिन्दु को तैयार करे और फिर उन वाद बिन्दु के आलोक में वैवाहिक याचिका पर निर्णय ले। यदि वाद बिन्दु को तैयार किया गया था, लेकिन विद्वान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था, तो उस स्थिति में भी, दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी वाद बिन्दु के अभाव में हैं, जिसके लिए साक्ष्य दर्ज किया गया था।

06. हालाँकि, ऐसा लगता है कि कोई वाद बिन्दु तैयार नहीं किया गया था, भले ही आदेश पत्र में इसका उल्लेख किया गया हो। इस तथ्य पर पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

07. इसके अलावा हमने देखा है कि इस मामले में कोई डिक्री तैयार नहीं की गई है क्योंकि यह विद्वत विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ–साथ पक्षों द्वारा हमारे सामने किए गए प्रस्तुतिकरण से प्रतीत होता है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) में निर्धारित किया गया है कि परिवार न्यायालय के फैसले या आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि विविध अपील के शीर्षक के तहत व्यवहार किए जाने के पीछे का उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित न्याय का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। परिवार

न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति से विधायी इरादा स्पष्ट है और डिक्री शब्द का लोप जानबूझकर और इरादतन किया गया है। इसके अलावा विद्वान वकील ने दलील दी कि यह मुद्दा अब विचारणीय नहीं रह गया है क्योंकि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सुनीता कुमारी बनाम प्रेम कुमार और ब्रज किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य के मामले में **2009(3)** पीएलजेआर **990** में रिपोर्ट करके इस वाद बिंदु का निपटारा कर दिया है। विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में हमें उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ–15 का हवाला दिया। पैराग्राफ–15 में निम्नलिखित लिखा है:–

> *"15.* उपरोक्त चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि परिवार न्यायालय अधिनियम *1984* की धारा *19* के तहत अपील को मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एआईआर करते हुए डिक्री के खिलाफ अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा *19* के तहत प्रावधानों का एक व्यापक दायरा है ताकि उस धारा के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा अपील योग्य सभी प्रकार के निर्णयों और आदेशों को शामिल किया जा सके, न कि केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित फरमानों को। इसलिए, इन अपीलों और इसी तरह की अन्य लंबित अपीलों को विविध अपीलों के रूप में माना जाना चाहिए, न कि प्रथम अपील के रूप में।"

08. इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा कानून के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, डिक्री के अभाव में भी, परिवार न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी जा सकती है और उक्त अपील को विविध अपील के रूप में माना जाएगा।

09. साथ ही, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में वाद बिंदु को तैयार न करने का कोई भौतिक महत्व नहीं है क्योंकि पक्षकार हमेशा विवाद के वाद बिंदु पर स्पष्ट थे और उन्होंने केवल उस प्रभाव के लिए अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने परिवार न्यायालय के समक्ष अपने तर्क के समर्थन में अपना साक्ष्य रखा, जबकि उत्तरवादी ने इसका खंडन किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद बिंदु की अनुपस्थिति मामले के लिए घातक है या जिसने मुकदमे को दूषित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप गलत सुनवाई हुई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने एआईआर **1963** एससी **884** में दर्ज नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम सम्पति सुब्बा राव के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने विद्वान परिवार

न्यायालय के निर्णय को अनेक आधारों पर चुनौती दी है तथा यद्यपि वाद बिंदु को न तय करने का तथ्य अपीलकर्ता के पक्ष में है, फिर भी अपीलकर्ता ने वाद बिंदु को तय करने तथा नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामले को विद्वान परिवार न्यायालय के पास वापस भेजने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि यह न्यायालय मामले में आगे बढ़ सकता है, तथा यदि वह चाहे तो अपने निर्धारण के लिए बिन्दु तैयार कर सकता है तथा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अपने द्वारा तैयार किए गए बिंदुओं के आलोक में अपील का अंतिम रूप से निपटारा कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त सरोजा बी.आर. बनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , बंगलौर तथा एक अन्य के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट 1988 एससीसी ऑनलाइन कर्नाटक 419 में दी गई थी, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना था कि परिवार न्यायालय के लिए वाद बिंदु को तय करना अनिवार्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय (रांची पीठ) द्वारा भास्कर गांगुली उर्फ़ वासकर गांगुली एवं एक अन्य बनाम सुजीत कुमार गुप्ता मामले में 1995 (2) पीएलजेआर 563 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पक्षों के बीच विवाद के लिए सही निर्णय पर पहुंचने के लिए वाद बिंदु को तैयार किया जाता है ताकि मतभेद के वास्तविक और पर्याप्त बिंदुओं को इंगित किया जा सके और साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जा सके कि प्रक्रिया के नियम न्याय प्राप्त करने के लिए बनाए गए उपकरण हैं न कि न्याय के मार्ग में बाधा डालने वाले उपकरण।

10. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क का प्रतिवाद उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय को वाद बिंदु को तैयार करना चाहिए था और तभी उसे मामले का निर्णय लेना चाहिए था।

11. चूंकि वाद बिंदु को न तय करना वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम इस वाद बिंदु पर शुरू में ही चर्चा करना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है (ऊपर), यह ऐसा मामला नहीं है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई वाद बिंदु बिल्कुल भी तैयार नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वाद बिंदु निश्चित बिंदु पर तैयार नहीं किया गया था और एक अन्य वाद बिंदु जो तैयार किया गया था वह विस्तृत नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने मामले में, स्पष्ट रूप से विद्वान परिवार

न्यायालय ने किसी भी वाद बिंदु को तैयार नहीं किया और फिर भी यह मामले का फैसला करने के लिए गया, हालांकि, पक्षों ने अपनी दलीलों में उठाए गए विवाद के पक्ष और विपक्ष में अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसलिए, यह माना जा सकता है कि पक्षकारों को वाद बिंदु के तथ्यों के बारे में पता था और तदनुसार उन्होंने अपना साक्ष्य रखा। इसके अलावा, वैवाहिक मुकदमा वर्ष 2013 में दायर किया गया था और तब से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। इसलिए, यह पक्षकारों के लिए कठोर होगा, यदि उन्हें इतने समय बीतने के बाद फिर से परिवार न्यायालय के मुकदमों और परेशानियों में डाल दिया जाये । इसलिए, हम महसूस करते हैं कि यह न्यायालय निर्धारण के बिंदुओं को तैयार करने के बाद साक्ष्य पर विचार कर इस अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है और जैसा कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 17 में परिकल्पित है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि परिवार न्यायालय के निर्णय में मामले का एक संक्षिप्त विवरण, निर्धारण का बिंदु, निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण शामिल होंगे।

12. उपर्युक्त चर्चा में दो कमियों का ध्यान रखा गया है, अर्थात् डिक्री तैयार न करना और विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष वाद बिंदु को तैयार न करना।

13. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर वर्तमान अपील के निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किए गए हैं:–

(i) क्या अपीलार्थी रविकांत का विवाह प्रत्यर्थी बंदना कुमारी के साथ उनकी सहमति के बिना और दबाव, धमकी और जबरदस्ती के तहत किया गया था?

(ii) क्या अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह धार्मिक और प्रथागत संस्कारों और अनुष्ठानों के उल्लंघन में किया गया था?

(iii) क्या अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह उपरोक्त आधारों पर रद्द किया जा सकता है?

14. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से कुल चार गवाहों से पूछताछ की गई है, जबकि उत्तरवादी की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। अ.सा.–1, चंद्र मौलेश्वर प्रसाद सिंह अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के पिता हैं। अ.सा.–2, रविकांत इस मामले के अपीलार्थी/याचिकाकर्ता हैं। अ.सा.– 3, सत्येंद्र कुमार सिंह याचिकाकर्ता के चाचा हैं। अ.सा.– 4 संजय कुमार याचिकाकर्ता के मामा हैं।

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की ओर से कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:–

15. प्रदर्श–I– जिला सैनिक बोर्ड लखीसराय को पत्र संख्या 1571489/रविकांत दिनांक 31.07.13 की फोटो प्रति, प्रदर्श–II–ए, पत्र संख्या 1571489/रविकांत दिनांक 23.07.13 की फोटो प्रति, प्रदर्श–III–ए, जिला आयुक्त लखीसराय को पत्र संख्या 15714892 ए/डीएसआर/सिविल दिनांक 25.07.13 की फोटो प्रति, प्रदर्श–IV–ए, रविकांत द्वारा 11.07.13 को कमांड ऑफिसर 28 इंफेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट, प्रदर्श–V– प्राथमिकी लखीसराय थाना केस संख्या 20/14 को दिए गए आवेदन की फोटो प्रति तथा प्रदर्श–VI–सत्येंद्र सिंह द्वारा 431 सी/13 के तहत दायर की गई शिकायत याचिका।

16. अब, अ.सा. 2 और अ.सा. 3 वे व्यक्ति हैं जो इस मामले में सीधे शामिल हैं। अपने मुख्य परिक्षण में अ.सा.–2 ने कहा है कि जून 2013 में, वह जम्मू और कश्मीर में तैनात थे जहाँ वे सेना की नौकरी में थे। 30 जून 2013 को वे अपने चाचा सत्येंद्र कुमार सिंह के साथ भगवान शिव की पूजा करने के लिए अशोक धाम मंदिर गए। पूजा के लिए सामान खरीदते समय, उन्हें राजेश कुमार, दीपक कुमार, बिपिन सिंह और अन्य लोगों ने घेर लिया, और चाकू और पिस्तौल की नोक पर, उन्होंने याचिकाकर्ता और उसके चाचा को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गए जहाँ उत्तरवादी को लाया गया और याचिकाकर्ता को उसके माथे पर सिंदूर लगाने के लिए कहा गया। जब याचिकाकर्ता ने इनकार कर दिया, तो उस पर थप्पड़ और मुट्ठी से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। अ.सा. 2 ने आगे बताया कि उसके चाचा को बंदूक की नोक पर अलग से बंधक बनाकर रखा गया था। इसके बाद, बिना किसी संस्कार और अनुष्ठान के और गवाह की इच्छा के खिलाफ, उन्हें उत्तरवादी के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद, गवाह और उत्तरवादी को एक अंधेरे कमरे में रखा गया जो बंद था और शौचालय जाने के बहाने, गवाह अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया जो बाहर रखी गई थी। गवाह ने आगे कहा कि वह लखीसराय पुलिस स्टेशन गया और एक लिखित रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह उत्तरवादी के पिता के साथ मिलीभगत में था। इसके बाद गवाह उसके घर आया। गवाह ने आगे बयान दिया है कि चूंकि उसे अपनी नौकरी में शामिल होना था क्योंकि उसकी छुट्टी की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए

वह अपनी नौकरी में शामिल होने गया और जब उसे आगे की छुट्टी दी गई, तो वह वापस आया और वर्तमान मामला दायर किया। गवाह ने आगे कहा कि चूंकि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए गवाह के चाचा ने उपरोक्त नामित व्यक्तियों के खिलाफ लखीसराय अदालत में 431 सी/12 का परिवाद मामला दर्ज किया। गवाह ने यह भी बयान दिया है कि सूर्यास्त के बाद, उसके चाचा को यह कहते हुए छोड़ दिया गया था कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी के बीच विवाह संपन्न हो गया है और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को उत्तरवादी के लिए कपड़े और गहने लाने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि याचिकाकर्ता के चाचा भी कैद से मुक्त होने के बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। गवाह ने आगे बयान दिया है कि जबरन सिंदूर लगाना धार्मिक परंपराओं और प्रथा के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है, क्योंकि उपरोक्त विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ और उसकी सहमति के बिना जबरन किया गया था और गवाह को जीवन की धमकी देते हुए किया गया था। चूंकि शादी जबरन की गई थी, इसलिए उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गवाह ने आगे बयान दिया है कि उत्तरवादी कभी भी अपने घर नहीं गया और याचिकाकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य ने अदालत के अलावा कहीं भी उत्तरवादी को नहीं देखा था। तथाकथित विवाह के बाद, गवाह ने अदालत के अलावा उत्तरवादी को कभी नहीं देखा। वास्तव में, गवाह ने तथाकथित विवाह से पहले भी उत्तरवादी को कभी नहीं देखा था और वह उसे या उस गाँव को भी नहीं जानता था जिससे वह संबंधित है। गवाह ने उत्तरवादी के इस दावे से इनकार किया कि वह शादी के बाद अपने ससुराल चली गई और उसने अपने परिवार द्वारा शादी में 10,00,000/– रुपये खर्च करने से भी इनकार किया और आगे इस बात से भी इनकार किया कि शादी हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार हुई थी। गवाह ने दहेज की मांग से भी इनकार किया है। गवाह ने उत्तरवादी के इस दावे से भी इनकार किया कि गवाह ने उसे उपहार के रूप में दिए गए 10,00,000/– रुपये हड़पने के लिए यह मामला दर्ज कराया है और गवाह ने दावा किया कि यह कहना गलत है कि शादी में 10,00,000/– रुपये का सोना और अन्य चीजें दी गई थीं।

17. तथ्य के लगभग समान अ.सा.–3 का साक्ष्य है जो अपीलार्थी के साथ एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने अ.सा.– 2 के साथ गवाही दी थी। अ.सा.–1 और अ.सा.–4 चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन वे बाद की घटनाओं के गवाह हैं और

उन्होंने अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया और अन्य गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि की। हालाँकि, अपने साक्ष्य में, दोनों ने बयान दिया कि उत्तरवादी का दावा है कि वह शादी के बाद अपने वैवाहिक घर गई थी और रु 10,00,000–शादी पर खर्च किया गया था। इन गवाहों ने इस बात से इनकार किया है कि अ.सा.–1 ने दहेज की मांग की थी और जब उसे नहीं दिया गया था, तो यह झूठा मामला शुरू किया गया था।

18. अब जब अ.सा.– 1 से विस्तार से जिरह की गई तो विवाह के आयोजन से संबंधित सुझावों से इनकार करने के अलावा दहेज की मांग और कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई। तथ्य के समान अ.सा.–1, अ.सा.–3 और अ.सा.– 4 की प्रतिपरीक्षण है और प्रत्यर्थी अपने पक्ष में कुछ सुझाव देने के अलावा प्रतिपरीक्षण से कुछ भी नहीं निकाल पाई है।

19. प्र.सा.–1 बमबम सिंह स्वतंत्र गवाह हैं, प्र.सा– 2 बंदना कुमारी स्वयं उत्तरवादी हैं और प्र.सा.–3 छोटेलाल पंडित स्वतंत्र गवाह हैं।

20. प्रत्यर्थी की ओर से कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए गए हैं जो इस प्रकार हैंः–

(i) काशीचक थाना कांड संख्या 52/17, दिनांक 04.07.17 की प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति।

(ii) काशीचक (शाहपुर ओ.पी.) पी.एस. कांड संख्या 52/17 के अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

21. प्र.सा.–1 बाम्बम सिंह ने अपने मुख्य परिक्षण में कहा कि वह बंदना कुमारी को जानता है, जिनकी शादी हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार रविकांत के साथ 30.06.2013 पर हुई थी। गवाह ने आगे कहा कि वह शादी में मौजूद था। दूल्हे की ओर से 10-15 व्यक्तियों लगभग 02:00 बजे शादी में शामिल हुए थे। अशोक धाम मंदिर में शादी के अनुष्ठान किए गए और रात को 10-11 बजे सप्तपदी का अनुष्ठान किया गया। दुल्हन की तरफ से एक छोटेलाल पंडित पंडित थे। शादी समारोह रात में लगभग 1 बजे समाप्त हुआ। शादी के बाद बंदना कुमारी अपने वैवाहिक घर चली गईं और वहां लगभग तीन-चार दिन रहीं। इसके बाद, बंदना कुमारी को रविकांत के चाचा के साथ उनके पैतृक घर भेज दिया गया। वे बंदना कुमारी को वहां नहीं ले गए क्योंकि उसके ससुराल वालों की ओर से 10,00,000 रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं हुई थी। अपनी प्रतिपरीक्षण में, गवाह ने गवाही दी कि वह बंदना कुमारी का प्रतिनिधि है। गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि

वह शादी के समय किसी भी पक्ष से मौजूद नहीं था। अशोक धाम में बंदना कुमारी की तरफ से 10 से 15 लोग थे और वह दूल्हे की तरफ से केवल चाचा सत्येंद्र कुमार को पहचानते थे। गवाह ने आगे बयान दिया है कि जिस समय सिंदूर लगाया जा रहा था, उस समय एक महिला मौजूद थी, लेकिन वह उस महिला का नाम नहीं बता सकता। गवाह ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों से शादी की रसीद ली गई थी, लेकिन उसने उन्हें रसीद लेते हुए नहीं देखा। गवाह ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया।

22. प्र.सा.–2 बंदना कुमारी स्वयं उत्तरवादी हैं। अपने मुख्य परिक्षण में, उन्होंने कथन किया है कि उनकी शादी हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के तहत रविकांत के साथ 30.06.2013 पर हुई थी और अशोक धाम मंदिर में पवित्र अग्नि के सात चरणों के बाद, शादी रविकांत की सहमति से सभी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए एक छोटेलाल पंडित द्वारा की गई थी। शादी में उनके पति रविकांत के अलावा उनके चाचा सत्येंद्र कुमार सिंह और 15–20 लोग भी बारात में शामिल हुए थे। शादी के बाद, उसे उसके पिता ने दूल्हे को सोने की चेन, अंगूठी, घरेलू सामान, कपड़े जैसे कई उपहार देकर उसके वैवाहिक घर भेज दिया और गवाह को 8 भर सोने के गहने और 20 भर चांदी के गहने और कपड़े आदि भी दिए गए। कुल 10,00,000–शादी पर खर्च किया गया था। गवाह अपने वैवाहिक घर गया और अपने पति के साथ 2–3 दिन बिताए, वहाँ उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले नाखुश थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला था और उन्होंने गवाह के पति और याचिकाकर्ता के चाचा पर भी गवाह को उसके माता–पिता के घर भेजने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके बाद, सत्येंद्र कुमार सिंह अपने भाइयों और रविकांत की माँ के दबाव में गवाह को उसके माता–पिता के घर ले गया। जब गवाह को उसके पिता और भाई द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद वापस नहीं लिया गया, तो गवाह ने याचिकाकर्ता, उसके माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज से संबंधित प्रतारणा के लिए विद्वान सी.जे.एम., लखीसराय की अदालत में 2015 का परिवाद मामला संख्या 593 सी के साथ एक परिवाद मामला दर्ज किया।

23. गवाह ने अपनी जिरह में इस आरोप का खंडन किया कि उसकी शादी जबरन की गई थी और वह उसके वैवाहिक घर नहीं गया था। हालांकि, उन्होंने बताया कि शादी की रस्में उनके घर पर ही निभाई गईं, लेकिन सिंदूर लगाने की

रस्म अशोक धाम में हुई। गवाह ने यह उल्लेख नहीं किया कि जब वह अपने वैवाहिक घर से लौटी, तो उसने कहा कि यह वर्ष 2013 में था, लेकिन उसे सही तारीख और महीना याद नहीं था। गवाह ने इस बात से इनकार किया कि उसकी शादी याचिकाकर्ता रविकांत के साथ जबरन की गई थी।

24. प्र.सा.–3, छोटेलाल पांडे वह पंडित है जो शादी को संपन्न करने का दावा करता है। अपने मुख्य परिक्षण में, इस गवाह ने गवाही दी है कि वह बंदना कुमारी को जानता है और उसके भाई ने गवाह को सूचित किया कि उसकी शादी रविकांत, ग्राम रावरा, थाना– काशीचक, जिला– नवादा के निवासी के साथ होनी थी। गवाह ने आगे कहा कि वह शाम को विवाह समारोह के लिए विपिन कुमार के घर गया था। उस समय तक बारात समारोह समाप्त हो चुका था। बारात के आने के बाद बिपिन सिंह के घर में सभी अनुष्ठान किए गए। गवाह ने आगे कहा कि अशोक धाम मंदिर में विवाह संपन्न हुआ था। शादी के समय घर के साथ–साथ पंडाल में भी दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। गवाह ने आगे कहा कि शादी समारोह 10–11 बजे तक चला। फोटोग्राफी भी की गई थी और वह तस्वीरों में मौजूद हैं। इस गवाह के कहने पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति के साथ प्रदर्श–ए से ए5 प्रदर्शित किए गए। गवाह ने आगे कहा कि शादी के अगले दिन उसने दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक–दूसरे से विदा लेते देखा और लड़की की विदाई भी हुई। गवाह ने आगे कहा कि शादी दुल्हन और दूल्हे की सहमति से की गई थी और इस सुझाव का खंडन किया कि शादी जबरन की गई थी। जिरह में गवाह ने गवाही दी कि उसे नहीं पता कि शादी में कितने अनुष्ठान किए जाते हैं। गवाह ने आगे कहा कि वह यह भी नहीं जानता कि विवाह में कितने वेदों का पाठ किया जाता है। गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसने किसी भी प्रयोगशाला से तस्वीरें नहीं लाई हैं और आगे कहा कि शादी में कोई तारीख निषिद्ध नहीं है। गवाह ने आगे कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि वहाँ कितनी बारातियाँ थीं और इस सुझाव का खंडन किया कि उसने रविकांत और बंदना कुमारी के विवाह को संपन्न नहीं किया था और झूठ बोल रहा था। गवाह ने इस बात से भी इनकार किया कि तस्वीरें जाली थीं और उसने गलत तरीके से इसकी पहचान की है। गवाह ने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि अशोक धाम में शादी होने के बारे में विवाद सही नहीं था क्योंकि उत्तरवादी ने उसके घर में शादी होने के बारे में कहा था।

25. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत यह समझने में विफल रही कि उत्तरवादी ने विवाह को रद्द करने के लिए वर्तमान मामला दायर करने के तीन साल बाद भ.द.स. के धारा 498 के तहत 2015 की परिवाद मामला संख्या 539 सी दायर किया है, जिसमें बेतुके और निराधार आरोप लगाए गए हैं। विद्वत निचली अदालत ने अपने लिखित बयान में उत्तरवादी के विरोधाभासी बयानों पर भी विचार नहीं किया है जिसमें उसने कहा है कि उसकी शादी उसके घर पर हुई थी, जबकि अपने बयान में उसने कहा है कि उसकी शादी अशोक धाम मंदिर में हुई थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रस्तुत की गई तस्वीर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और बल्कि वे साबित करते हैं कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्य शादी के समय मौजूद नहीं थे। फोटोग्राफर की जाँच नहीं की गई और तस्वीरें साबित नहीं हुईं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उत्तरवादी के मामले को प्र.सा–3 के साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था जो पंडित है और जिसने शादी करने का दावा किया था। यह गवाह सप्तपदी के प्रदर्शन के बारे में भी नहीं जानता था और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में प्रावधान है कि कोई भी विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि पवित्र अग्नि रीति-रिवाजों के आसपास सात कदम पूरे नहीं हो जाते। चूंकि अपीलकर्ता को गंभीर परिणामों की धमकी देकर उत्तरवादी के सिर पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया था और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ता का मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत आता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय का दृष्टिकोण पक्षपात को दर्शाता है और मामले का निर्णय लेते समय गलत कथन किया गया है। अ.सा.–2 की प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 37 और 38 की चर्चा, याचिकाकर्ता स्वयं, साक्ष्य की पूरी तरह से गलत सराहना है। इन दो अनुच्छेदों से यह कहीं भी सामने नहीं आता है कि विवाह अपीलार्थी की इच्छा से संपन्न किया गया था। निम्न न्यायालय इस महत्वपूर्ण वाद बिंदु पर निर्णय लेने में विफल रहा कि क्या विवाह याचिकाकर्ता की सहमति से किया गया था और क्या यह बल और जबरदस्ती के तहत था या क्या यह विवाह अपीलार्थी की स्वतंत्र सहमति से विधिवत किया गया था। विद्वत परिवार न्यायालय भी अपीलार्थी के मामले के समर्थन में सेना के अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रहा और विवादित निर्णय प्रासंगिक प्रदर्शनों पर विचार न करने और उन्हें खारिज करने से ग्रस्त है, अर्थात, प्रदर्श I, II, III और IV जो याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के मामले को स्पष्ट रूप से साबित

करते हैं। विद्वान परिवार न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में लाया गया था और न ही तस्वीरों की जांच की गई थी और न ही अशोक धाम मंदिर की रसीद दायर की गई थी। विद्वान परिवार न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलकर्ता के पिता भी विवाह के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार, विद्वान परिवार न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों और सामग्री की सराहना किए बिना वैवाहिक मामले को विकृत और मनमाने ढंग से खारिज कर दिया है।

26. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि इस अपील में शामिल वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी की सहमति स्वतंत्र थी या क्या यह बल द्वारा प्राप्त की गई थी। अपीलार्थी की स्वतंत्र सहमति के रूप में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए और एक बार परिस्थितियों और सामग्री से संकेत मिलता है कि सहमति स्वतंत्र नहीं थी या विवाह उत्तरवादी की इच्छा के खिलाफ किया गया था, तो वैवाहिक मामले की अनुमति दी जानी चाहिए थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान निचली अदालत ने कुछ स्पष्ट परिस्थितियों की अनदेखी की। मान लीजिए, अपीलार्थी के माता–पिता जीवित हैं, लेकिन वे दोनों उस समय मौजूद नहीं थे जब उनके बेटे की शादी हो रही थी और उत्तरवादी के अनुसार, यह सामान्य अरेंज मैरिज का मामला था। प्रत्यर्थी बयान देता है कि प्र.सा.–2 ने मुख्य परिक्षण के पैराग्राफ नंबर 3 में अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह अपीलार्थी के चाचा सत्येंद्र कुमार सिंह के संरक्षण में किया गया था। दूसरी ओर, निचली अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 17 में दर्ज किया है कि सत्येंद्र कुमार सिंह शादी के समय मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, वह अभिभावक भी अनुपस्थित था जिसके संरक्षण में कथित रूप से विवाह किया जा रहा था। यह भी स्पष्ट है कि प्र.सा.–3, पुजारी, अर्थात् छोटेलाल पंडित, जिन्होंने विवाह को संपन्न किया, उन्हें 'सप्तपदी' के बारे में कोई जानकारी नहीं है और नीचे के विद्वान अदालत ने कहा कि 'सप्तपदी' के अनुष्ठान नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि विवाह नहीं किया गया था। यह निष्कर्ष पूरी तरह से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप है और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **2001(7)** एस.सी.सी. **487** में अनुच्छेद संख्या 12–16 अपने निर्णय में कहा है कि हिंदू रूप में विवाह की परंपरा 'सप्तपदी' और 'दत्त होम' के प्रदर्शन के अभाव में वैध विवाह नहीं होगी। इसके अलावा इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है

कि अपीलार्थी के नामित रिश्तेदारों में से कोई भी शादी में शामिल हुआ था और अपीलार्थी की ओर से किसी भी विशिष्ट रिश्तेदार का नाम लिए बिना केवल 15 से 20 व्यक्तियों के अस्पष्ट आरोप हैं। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कानूनी और वैध विवाह का दावा करते हुए जबरन विवाह से इनकार करने वाले उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान बहुत ही गुप्त और अस्पष्ट है। विवाह के वैध निष्पादन के विवरण के संबंध में कोई विशिष्ट मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार यह भी टालमटोल करने वाला इनकार है और इसलिए इसे स्वीकार माना जाता है और विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2013(2) एससीसी 606 पैराग्राफ संख्या 23 से 25 में दिए गए निर्णय पर अपना भरोसा जताया है। ये सभी परिस्थितियां केवल इस निष्कर्ष पर ले जाएंगी कि विवाह सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया गया था जैसा कि उत्तरवादी द्वारा आरोप लगाया गया था। बल्कि परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि विवाह असामान्य परिस्थितियों में किया गया था और विवाह के लिए अपीलार्थी की सहमति एक स्वतंत्र सहमति नहीं थी, बल्कि यह बल द्वारा और उसकी इच्छा के खिलाफ प्राप्त की गई थी। एक बार, यह आरोप लगाया गया है कि विवाह हिंदू अधिकारों और अनुष्ठानों के अनुसार नहीं किया गया था और सप्तपदी के प्रदर्शन के बिना और बल का उपयोग करके, उत्तरवादी पक्ष को यह साबित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है कि विवाह सभी अनुष्ठानों का पालन करके सामान्य परिस्थितियों में विधिवत किया गया था और विवाह वैध था, लेकिन उत्तरवादी इस पहलू को साबित करने में विफल रहा और इस तरह वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वैवाहिक मामले को खारिज करने के लिए विद्वान निचली अदालत का वजन करने का मुख्य कारण घटना के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज करने में लगभग 16 दिनों की देरी है। हालांकि, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अपीलकर्ता और उसके चाचा ने घटना के तुरंत बाद लखीसराय पुलिस स्टेशन के समक्ष मामला दर्ज कराने की कोशिश की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था और इस बिंदु पर, वैवाहिक मामले में स्पष्ट दलील है जिसे विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था और यह इनकार टालमटोल वाला है और इस प्रकार आदेश 8, नियम 3 से 5 सीपीसी के तहत स्वीकारोक्ति माना जाता है। यही बात अ.सा.– 2 (पैरा 8 में) और अ.सा.– 3 (पैरा 6 में) द्वारा कही गई थी। निचली अदालत ने भी इस तथ्य के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कि अपीलार्थी की छुट्टी 04.07.2013 के बाद समाप्त हो रही

थी और इस तरह उसे भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी में शामिल होने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए रवाना होना पड़ा और वहां भी उसने मामले की सूचना दी और अपने कमांडेंट को दिनांकित 11.07.2013 पत्र द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए प्रार्थना की। इसके बाद, कमांडेंट के कार्यालय से, 23.07.2013 पर घटना के संबंध में मुख्यालय को एक पत्र लिखा गया। इसके बाद, अपीलार्थी के कमांडिंग अधिकारी ने लखीसराय के जिला आयुक्त को 25.07.2013 पर एक पत्र लिखा जिसमें उनसे एस.एच.ओ., लखीसराय पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा मामले की जांच के लिए कमांडेंट के कार्यालय से जिला सैनिक बोर्ड, जिला–लखीसराय को एक और पत्र भेजा गया। अंततः दिनांक 16.06.2013 को अपीलार्थी के चाचा द्वारा 2012 का शिकायत वाद संख्या 431 सी धारा 323, 341, 352, 387 एवं 365 भ.द.स. के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद, उक्त शिकायत मामले में, धारा 156 (3) द.प्र.स. के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया और उसके बाद, जांच शुरू की गई। इस प्रकार परिस्थितियों में, परिवाद मामला दर्ज करने में 16 दिनों की देरी स्पष्ट रूप से समझाई गई है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा कथित विवाह को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बलपूर्वक किया गया था तथा कम से कम अपीलकर्ता की स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया था।

27. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुति का जोरदार विरोध किया। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और उत्तरवादी का विवाह हिंदू विवाह संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार अशोक धाम में 30.06.2013 पर किया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि सप्तपदी के गैर–प्रदर्शन की कोई प्रासंगिकता नहीं है और वर्तमान मामले को शायद ही उतना प्रभावित करता है जितना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि यदि सप्तपदी नहीं की जाती है और अन्य समारोह दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि एक वैध विवाह संपन्न किया गया था। यद्यपि अपीलार्थी दावा करता रहा है कि विवाह संपन्न हो गया है, तथापि, उसके परिवार के सदस्यों के आचरण से इसकी पुष्टि नहीं होती है। उन्होंने स्थानीय पुलिस या अधिकारियों के समक्ष मामला दर्ज कराने का विकल्प नहीं चुना, हालांकि, यह स्वीकार

किया जाता है कि अपीलकर्ता के चाचा को उत्तरवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने विवाह के दौरान रिहा कर दिया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलार्थी का यह दावा कि वह घर से भाग गया और पुलिस को मामले की सूचना देने के बजाय, अपने कर्तव्य की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से अपना गाँव छोड़ दिया, अत्यधिक अविश्वसनीय लगता है। 2013 का 431 नंबर वाला परिवाद मामला अपीलार्थी के चाचा द्वारा केवल सबूत बनाने के लिए दायर किया गया था। याचिकाकर्ता पक्ष के किसी भी गवाह ने इस मामले को दर्ज करने में 16 दिनों की देरी के बारे में नहीं बताया है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए।

28. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के मामलों पर विचार करने से पहले, यहां प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा। याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(सी) के तहत अपनी शादी को रद्द करने के लिए मामला दायर किया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में रद्द किए जा सकने वाले विवाहों के लिए प्रावधान है, जो निम्नानुसार हैः–

> *"12.* शून्यकरणीय विवाह।– *(1)* इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी विवाह शून्यकरणीय होगा और उसे निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर शून्यता की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है, अर्थात्:–
>
> *[(क)* कि विवाह प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण संपन्न नहीं हुआ है*;* या*]*
>
> *(ख)* कि विवाह धारा *5* के खंड *(ii)* में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन है*;* या
>
> *(ग)* कि याचिकाकर्ता की सहमति, या जहां याचिकाकर्ता के विवाह में अभिभावक की सहमति *[*धारा *5* के तहत अपेक्षित थी, जैसा कि बाल विवाह निषेध *(*संशोधन*)* अधिनियम*, 1978 (1978* का *2)* के प्रारंभ होने से ठीक पहले था*] **, ऐसे अभिभावक की सहमति बलपूर्वक *[*या समारोह की प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य या परिस्थिति के बारे में धोखाधड़ी द्वारा*]* प्राप्त की गई थी*;* या
>
> *(घ)* कि उत्तरवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी
>
> *(2)* उप–धारा *(1)* में किसी बात के होते हुए भी, विवाह को रद्द करने के लिए कोई याचिका–
>
> *(क)* उपधारा *(1)* के खंड *(ग)* में निर्दिष्ट आधार पर विचार किया जाएगा यदि–
>
> *(i)* याचिका बल के बंद हो जाने या, जैसा भी मामला हो, धोखाधड़ी का पता चलने के एक वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई हो*;* या

(ii) याचिकाकर्ता ने, अपनी पूर्ण सहमति से, बल के बंद हो जाने या, जैसा भी मामला हो, धोखाधड़ी का पता चलने के बाद विवाह के दूसरे पक्ष के साथ पति या पत्नी के रूप में रह लिया हो;

(ख) उपधारा *(1)* के खंड *(घ)* में विनिर्दिष्ट आधार पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए–

(i) कि याचिकाकर्ता विवाह के समय आरोपित तथ्यों से अनभिज्ञ था;

(ii) कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले संपन्न विवाह के मामले में कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के बाद संपन्न विवाहों के मामले में विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर शुरू की गई है; और

(iii) कि याचिकाकर्ता की सहमति से वैवाहिक संभोग याचिकाकर्ता द्वारा [उक्त आधार] के अस्तित्व की खोज के बाद से नहीं हुआ है।"

29. याचिका याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की सहमति के अभाव के आधार पर विवाह को रद्द करने के लिए दायर की गई है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता/अपीलार्थी का विशिष्ट तर्क है कि उसकी सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई थी क्योंकि उसे बंदूक की नोक पर धमकी दी गई थी।

30. अब, मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे अपने चाचा के साथ अपहरण कर लिया गया था और जीवन के खतरे में शादी समारोह से गुजरने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि उसने और उसके चाचा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए लखीसराय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और, बाद में, 16.07.2013 को याचिकाकर्ता के चाचा ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्य के कृत्यों के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करने के लिए, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की ओर से स्पष्टीकरण आया है कि चूंकि वह एक सैनिक है और छुट्टी पर था, इसलिए उसकी छुट्टी की अवधि समाप्त हो रही थी और उसे अपने कर्तव्यों में शामिल होने की आवश्यकता थी, इसलिए वह अपने घर पर नहीं रह सकता था और अपने कार्य स्थल पर चला गया। यह तर्क पूरी तरह से योग्यता से विक्षिप्त नहीं है। याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने प्रदर्श के रूप में कई दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया है और ये दस्तावेज याचिकाकर्ता के अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को पत्र और संचार हैं। यहां तक कि प्रदर्शनी–(।)

से प्रदर्शनी (IV)–ए भी याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करता है और दस्तावेज 11 जुलाई, 2013 से 31 जुलाई, 2013 तक पाए जाते हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से उसके खिलाफ कुकर्म की रिपोर्ट करने में अनुचित देरी हुई थी। साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की छुट्टी की कमी के कारण अपने कार्यस्थल से जाने की कहानी विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, मामला संख्या 431(सी) के माध्यम से याचिकाकर्ता के चाचा द्वारा दायर शिकायत याचिका प्रदर्शनी–VI है और प्रदर्शनी–V 2014 के लखीसराय थाना मामला संख्या 20 की प्राथमिकी है, जो शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

31. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ एक सामान्य विवाह का दावा किया है, लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों और साक्ष्यों से भी विवाह सामान्य के अलावा कुछ भी प्रतीत होता है। यदि यह एक सामान्य अरेंज मैरिज होती, तो स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों की भागीदारी होती। याचिकाकर्ता के चाचा को छोड़कर, उत्तरवादी द्वारा किसी अन्य रक्त संबंधियों या याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों के नाम रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं, जो शादी में शामिल हुए होंगे। प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि 15–20 लोग याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की ओर से शादी में शामिल हुए थे, लेकिन इन व्यक्तियों के नाम उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं। हम अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में योग्यता पाते हैं कि अन्य करीबी रिश्तेदार उत्तरवादी के संस्करण के अनुसार भी विवाह में शामिल नहीं हुए थे और यह दर्शाता है कि यह एक असामान्य विवाह था, भले ही उत्तरवादी के विवाद को ध्यान में रखा जाए।

32. एक बार जब याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि उसे विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है और विवाह रीति–रिवाजों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और इसके बाद उत्तरवादी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, तो उत्तरवादी पर यह दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता के तर्क का खंडन करते हुए दिखाए कि विवाह सभी रीति–रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था और यह एक सामान्य विवाह था। हालाँकि, ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य उत्तरवादी के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी इस तर्क का खंडन करने में पूरी तरह विफल रहा है कि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी के पक्ष ने विवाह के स्थान के बारे में भी पूर्वाग्रह व्यक्त किया है। एक समय यह दावा किया गया है कि

विवाह उत्तरवादी के घर पर किया गया था, जबकि दूसरी ओर, गवाहों के साक्ष्य में यह आया है कि विवाह अशोक धाम मंदिर में किया गया था। यदि प्रत्यर्थी के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तो मंदिर में विवाह के अनुष्ठान के लिए कोई रसीद दर्ज नहीं की गई थी, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि ऐसी रसीदें जारी की जा रही थीं। यह भी प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि रसीद ली गई थी और वह खो गई थी।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का यह मामला हमेशा से रहा है कि उसे बंदूक की नोक पर शादी के लिए मजबूर किया गया था और जबरन शादी की बात याचिकाकर्ता के अधिकारी द्वारा विभिन्न अधिकारियों के साथ किए गए संचार से पता चलती है और याचिकाकर्ता के सभी गवाहों ने बिना किसी विरोधाभास के इस बिंदु पर याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया है। यहां तक कि उत्तरवादी भी याचिकाकर्ता के गवाहों से अपने पक्ष में कुछ जवाब हासिल करने में विफल रहा है। कुछ नीरस सुझाव देने के अलावा, उत्तरवादी याचिकाकर्ता के गवाहों के मुंह से अपने पक्ष में कुछ भी नहीं निकाल पाया है।

33. दोनों पक्षों की यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के विवाह के अनुष्ठान की दिशा में कुछ समारोह किया गया था। लेकिन, यह एक वैध विवाह की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए।

34. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में निम्नलिखित लिखा है:–

> *"7.* हिंदू विवाह के लिए समारोह।– *(1)* हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है। *(2)* जहां ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी *(*अर्थात, वर और वधू द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष संयुक्त रूप से सात कदम उठाना*)* शामिल है, वहां सातवां कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।"

35. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब सप्तपदी सहित ऐसे संस्कार और समारोह होते हैं तो सातवां चरण पूरा होने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। इसके विपरीत, यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। अब, उत्तरवादी ने दावा किया है कि सभी अनुष्ठान किए गए थे और सप्तपदी पूरी हो गई थी। यह आश्चर्यजनक है कि विवाह समारोह संपन्न कराने वाले पंडित को विवाह की अनिवार्यताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका बयान विवाह के स्थान के बारे में स्पष्ट नहीं है। कथित विवाह की तस्वीरें उत्तरवादी के

मामले में मदद नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें ठीक से प्रदर्शित नहीं किया गया है और उन्हें स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, उनकी तस्वीरों से कुछ भी पता नहीं चल सका। याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता का यह मामला नहीं है कि कोई विवाह कभी संपन्न नहीं हुआ बल्कि उनका तर्क है कि उन्हें विवाह के लिए मजबूर किया गया था। इन परिस्थितियों में, भले ही तस्वीरों को ध्यान में रखा जाए, यह नहीं कहा जा सकता कि विवाह बिना किसी बाहरी प्रभाव के संपन्न हुआ था। याचिकाकर्ता का हमेशा से यह तर्क रहा है कि उसका विवाह दबाव में हुआ था और यह खंडनीय तर्क था, जिसके लिए उत्तरवादी पर जिम्मेदारी थी, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रही। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के मामले को उन गवाहों द्वारा समर्थित किया गया है, जो जिरह के दौरान बेदाग रहे।

36. विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले पर अविश्वास करने के लिए अपना स्वयं का तर्क अपनाया है, लेकिन, हमारी राय में, उक्त दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। विद्वान परिवार न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता ने तुरंत पुलिस या न्यायालय में शिकायत दर्ज नहीं कराई और यह अंतर याचिकाकर्ता के मामले को अविश्वसनीय बनाता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता ने स्थिति स्पष्ट की है और कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई है, यहां तक कि याचिकाकर्ता ने सेना कमान में अपने अधिकारी के माध्यम से विवाह के बाद कदम उठाए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता मामले को लेकर सो गया था। इसी तरह, विद्वान परिवार न्यायालय ने दर्ज किया है कि विवाह के समय दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। लेकिन, परिवार न्यायालय इस निष्कर्ष पर कहां से पहुंचा, यह उत्तरवादी पक्ष के साक्ष्य से पता नहीं चलता है। जब विद्वान परिवार न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की कि तस्वीरों की जांच नहीं की गई है, तो परिवार न्यायालय के लिए उन्हीं दस्तावेजों पर भरोसा करना खुला नहीं था। फिर, अन्यथा कोई सबूत न होने की स्थिति में, विद्वान परिवार न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सप्तपदी की रस्में निभाने का यह अर्थ नहीं है कि विवाह नहीं हुआ, किसी भी तरह से निराधार है। विद्वान परिवार न्यायालय ने एक और पहलू पर विचार किया है, वह है उत्तरवादी का कुछ दिनों तक अपने ससुराल में रहना। लेकिन, इस दावे को साबित करने के लिए सबूत कहां है? किसी भी सहायक सबूत के अभाव में यह केवल एक बयान है। यदि उत्तरवादी अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है, तो उसके पास पुष्टि करने वाले सबूत होने चाहिए थे, जो वर्तमान मामले में स्पष्ट

रूप से कमी है। इसके अलावा, विद्वान परिवार न्यायालय ने उत्तरवादी द्वारा भ.द.स. की धारा 498 (ए) के तहत मामला दर्ज कराने पर भरोसा किया। लेकिन, तारीखों और घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा मामला 17.08.2015 को दर्ज कराया गया था, यानी शादी के दो साल बाद। यह संयोग नहीं है कि उक्त मामला वैवाहिक मामला संख्या 51/2013 के अस्तित्व में आने के बाद दर्ज किया गया। इसलिए, धारा 498(ए) भ.द.स. के तहत मामला वैवाहिक मामले का जवाबी हमला होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

37. हम याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क में योग्यता पाते हैं। उत्तरवादी का लिखित बयान कई बिंदुओं पर मौन है और खंडन टालमटोल वाला है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पक्ष के साक्ष्य में यह भी आया है कि विवाह शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी शादी की रात भाग गया था और तब से कोई सहवास नहीं हुआ था। यहां तक कि उत्तरवादी द्वारा भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है, हालांकि एक याचिका दायर की गई है कि वह शादी के बाद अपने वैवाहिक घर गई थी, लेकिन जैसा कि पहले देखा गया है कि वह कोई पुष्टि करने वाला सबूत पेश करने में विफल रही। ज्ञान चंद और ब्रदर्स एवं एक अन्य बनाम रतन लाल उर्फ रतन सिंह, **2013(2)** एससीसी **606** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है कि यदि कोई विशिष्ट इनकार नहीं है और इनकार पूरी तरह से टालमटोल वाला है, तो उत्तरवादी को कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसी तरह, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी **(2001) 7** एससीसी **487** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना बिल्कुल उचित है कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप 'सप्तपदी' और 'दत्त होम' के प्रदर्शन की अनुपस्थिति में वैध विवाह नहीं है।

38. अब तक की गई चर्चाओं के आलोक में और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है और इसलिए 2013 के वैवाहिक मामले संख्या 51 में पारित 27.01.20. दिनांकित निर्णय को दरकिनार किया जाता है । अपीलार्थी–याचिकाकर्ता का प्रत्यर्थी के साथ विवाह रद्द किया जाता है।

39. तदनुसार, विविध अपील को अनुमति दी जाती है।

40. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/हिमांशु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।